पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आनंद कुमार सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4860

13 दिसम्बर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता को बिना किसी नियमित विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त करना, केवल इस आधार पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत ऐसा करना "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था", कानूनी रूप से टिकने योग्य है।

हेडनोट्स

सेवा कानून – संविधान का अनुच्छेद 311(2)(बी) – बिना जांच के बर्खास्तगी – वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बिना आह्वान – रद्द –

संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) का इस्तेमाल करके विभागीय जांच के बिना पुलिस अधिकारी (याचिकाकर्ता) को बर्खास्त करना उचित नहीं है, क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई सामग्री या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। सतर्कता एफआईआर या निलंबन आदेश का संदर्भ मात्र जांच से छूट देने का औचित्य नहीं है।

[पैरा 13, 21, 26, 27]

अनुशासनात्मक कार्यवाही – बिहार सीसीए नियम, 2005 – नियम 20(ii) – विवेक का प्रयोग न करना – अनुपालन न करने से आदेश अमान्य हो जाता है –

यह माना गया कि प्राधिकारी बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के नियम 20(ii) के आदेश का पालन करने में विफल रहा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डी.आई.जी.) द्वारा संतुष्टि की कोई स्वतंत्र या वस्तुनिष्ठ रिकॉर्डिंग नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जांच करना अव्यावहारिक था।

[पैरा 20, 21, 24]

आपराधिक कानून – अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत – प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं – विभागीय कार्रवाई विफल –

माना गया कि, सहार पीएस केस संख्या 123/2021 में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने वाला अंतिम फॉर्म प्रस्तुत किया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया,

अनुशासनात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार करने के लिए एक वैध आधार बनाता है, खासकर जब कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी।

[पैरा 25]

भारत का संविधान – प्राकृतिक न्याय – अनुच्छेद 14 – अवसर के बिना बर्खास्तगी – उल्लंघन –

न्यायालय ने कहा कि बिना जांच और बचाव का अवसर दिए किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। **[पैरा 22]**

न्याय दृष्टान्त

कृष्णकांत बी. परमार बनाम भारत संघ , (2012) 3 एससीसी 178 - [पैरा 13]; *अवतार सिंह बनाम भारत संघ* , (2016) 8 एससीसी 471 - [पैरा 14]; *भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल* , (1985) 3 एससीसी 398 – [पैरा 15-17]; *वेद मित्तर गिल बनाम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़* , (2015) 8 एससीसी 86 – [पैरा 19];***तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य* , (2006) 13 एससीसी 581 - [पैरा 22]**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

जांच के बिना बर्खास्तगी; अनुच्छेद 311(2)(बी); नियम 20(ii) बिहार सीसीए नियम; प्राकृतिक न्याय; अंतिम रूप; निगरानी मामला; बर्खास्तगी आदेश को रद्द करना; विभागीय कार्यवाही से छूट; डीआईजी; संतुष्टि का अभाव

प्रकरण से उत्पन्न

सहार थाना कांड संख्या 123/2021 में कथित कदाचार के संबंध में डीआईजी, शाहाबाद रेंज, आरा द्वारा विभागीय जांच किए बिना पारित बर्खास्तगी आदेश दिनांक 08.07.2021 को अपीलीय आदेश दिनांक 02.11.2022 द्वारा पुष्टि की गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए: श्री बिन्ध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विपीन कुमार सिंह, अधिवक्ता, सुश्री स्मृति सिंह, अधिवक्ता, सुश्री निकिता मित्तल, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री पी.के. वर्मा, एएजी-3

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 सिविल रिट क्षेत्राधिकार याचिका संख्या 4860

==========

आनंद कुमार सिंह पिता- स्वर्गीय कामेश्वरी प्रसाद सिंह, निवासी- गाँव-सहारी, थाना- बाढ़, जिला-पटना

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील और कल्याण), बिहार, पटना।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था), बिहार, पटना।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डेहरी-ऑन-सोन।
6. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विपिन कुमार सिंह, अधिवक्ता
सुश्री स्मृति सिंह, अधिवक्ता
सुश्री निकिता मित्तल, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री पी. के. वर्मा, (एएजी 3)

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह
मौखिक निर्णय
तारीखः13-12-2024

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बिन्ध्याचल सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह, सुश्री स्मृति सिंह और सुश्री निकिता

मित्तल तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. वर्मा, विद्वान ए.ए.जी.3 को सुना गया।

राहत

2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या-1 में, अन्य बातों के *साथ-साथ*, निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई है, जिन्हें इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *i) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किया गया पत्र संख्या 4460 दिनांक 25.06.2021 को रद्द करे ,जिसके तहत सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (इसके बाद सी सी ए नियम, 2005 के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित नियमित विभागीय कार्यवाही किए बिना भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है।*
>
> *ii) उत्प्रेषण प्रकृति में रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जो उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डेहरी-ऑन-सोन द्वारा पारित आदेश को रद्द करे, जो ज्ञापन संख्या 1708 दिनांक 08.07.2021 में निहित है। जिसके तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दिनांक 08.07.2021 से सेवा से बर्खास्त करते हुए यह कारण दिया कि याचिकाकर्ता को भगोड़े घोषित करके नियमित विभागीय कार्यवाही करना अव्यावहारिक है, जबकि इस तरह के गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई उचित आधार नहीं है।*
>
> *iii) उत्प्रेषण प्रकृति में रिट, या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने हेतु, जो पुलिस अधीक्षक भोजपुर जिला आदेश संख्या संख्या 2140 दिनांक 10.07.2021 के तहत जारी परिणामी आदेश को रद्द करे।*
>
> *iv) उत्प्रेषण प्रकृति में रिट, या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने हेतु, जो अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिनांक 02.11.2022 के आदेश को रद्द करे, , जिसके*

तहत याचिकाकर्ता द्वारा की गई विभागीय अपील को उक्त अपीलीय आदेश में कोई भी कारण के बिना और केवल अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करके खारिज कर दिया गया है।

v) यह घोषित करने हेतु कि प्रतिवादी प्राधिकारी इस गलत निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि याचिकाकर्ता के मामले में नियमित विभागीय कार्यवाही करना अव्यावहारिक है और केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का सहारा लेकर यह अभिनिर्धारित करना कि याचिकाकर्ता भगोड़ा रहा है, यह समझे बिना कि याचिकाकर्ता लगातार मौजूद है और कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार है, यदि कोई हो।

vi) यह अभिनिर्धारित करने के लिए 3/36 भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित बर्खास्तगी का आदेश केवल दिखावा है और सी सी ए नियम, 2005 के साथ-साथ बिहार पुलिस नियमावली सहित संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता कभी फरार नहीं रहा है।

vii) किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने के लिए जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझते हैं।

संक्षिप्त तथ्य

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को सहार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और जब वह इस अवधि के दौरान तैनात था, तो संजय यादव नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 05.06.2021 को एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अशोक सिंह नामक व्यक्ति द्वारा रात में रेत से भरे ट्रक से पैसे एकत्र किए गए थे, जो याचिकाकर्ता के लिए ट्रक चालक से पैसे वसूल कर रहा था और इस तरह के आरोप के आधार पर सहार थाना कांड संख्या- 123/2021 दिनांक 06.06.2021 प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता और एक अशोक सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 384, 385, 420,

388, 504, 506 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर, उसे दिनांक 06.06.2021 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद, प्रपत्र संख्या 4460 के माध्यम से एक सिफारिश की गई थी। जो दिनांक 25.06.2021 को पुलिस अधीक्षक, भोजपुर द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी। बिना किसी भी नियमित विभागीय जांच के जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) और बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (इसके बाद 'बिहार सी सी ए नियम, 2005' के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित। अनुशंसा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता फरार था और उसी के आलोक में अनुच्छेद 311 (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित विभागीय कार्यवाही करना उचित रूप से अव्यवहारिक है। इसके बाद, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई सिफारिश के बाद, उप महानिरीक्षक (इसके बाद संक्षेप में डी. आई. जी. के रूप में संदर्भित), शाहाबाद क्षेत्र, डेहरी-इन-सोन द्वारा एक आदेश पारित किया गया। ज्ञापंक संख्या 1708 दिनांक 08.07.2021, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 08.07.2021 से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें यह कारण बताया गया है कि याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित करके नियमित विभागीय कार्यवाही करना अव्यावहारिक है। डी आई जी द्वारा पारित आदेश के अनुसार, एक परिणामी भोजपुर जिला आदेश सं-2140 दिनांक 10.07.2021 पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के कार्यालय से जारी किया गया था। बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 30.09.2021 पर एक अपील को प्राथमिकता देते हुए अनुरोध किया कि वह एक नियमित विभागीय कार्यवाही का हकदार है ताकि वह आरोप/आरोपों पर अपना जवाब दाखिल कर सके। ताकि वह अपने पक्ष में सफाई दे सके, जिससे उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को दिनांक 02.11.2022 के आदेश के

माध्यम से खारिज कर दिया। बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश से व्यथित, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

4. वर्तमान रिट याचिका में पारित दिनांक 12.12.2024 के आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक, (भोजपुर), श्री राज, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पक्षकारों की दलीलें

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सहार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और जब वह उक्त अवधि के दौरान तैनात था, तो संजय यादव द्वारा दिनांक 05.06.2021 को एक लिखित शिकायत पर ट्रक चालकों से पैसे ऐंठने के आरोप में याचिकाकर्ता और एक अशोक सिंह के खिलाफ एक प्राथमिकी सहार थाना कांड संख्या - 123/2021 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को अनावश्यक आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा और याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और उन्हें अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी ठोस कारण के बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता की पीठ पीछे अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और बिहार सी सी ए नियम, 2005 के नियम 20 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए, उन्हें कथित आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता फरार था और नियमित विभागीय कार्यवाही करना व्यावहारिक नहीं था।

6. विद्वान वकील ने आगे कहा कि सहार थाना कांड संख्या- 123/2021, में जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, याचिकाकर्ता को निर्दोष पाते हुए अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया और तदनुसार, विशेष न्यायाधीश सतर्कता,

पटना ने विशेष मामला संख्या 22(ए)/2021 (सहार(भोजपुर) थाना कांड संख्या 123/2021 से उत्पन्न) में पारित दिनांक 03.10.2024/04.10.2024 के आदेश के अनुसार कार्यवाही को समाप्त कर दिया। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत अंतिम प्रपत्र को अभिलेख पर लाया है और पूरक शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 5 में विशिष्ट जानकारी दी है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में निर्दोष पाया गया है और विद्वान न्यायाधीश ने कार्यवाही बंद कर दी है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई में कानून के अनुसार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

7. राज्य सरकार की ओर से श्री पी. के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता-3 (ए. ए. जी.-3), 7/36 ने, ऊपर बताए गए स्वीकृत तथ्यों की पृष्ठभूमि में, संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद 311 (2) (बी) में निहित इसके अधिदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में, याचिकाकर्ता पर सहार थाना कांड संख्या 123/2021 जो उसके खिलाफ दर्ज किया गया था, में आरोप लगाया गया था,कि वह रेत खनन माफियाओं से अवैध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा गंभीर आरोप, जो एक अनुशासन सेवा में था, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक था और तदनुसार बिहार सी सी ए नियम, 2005 के नियम 20 का सहारा लेते हुए, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि बिहार सी सी ए नियम, 2005 के नियम 20 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और यह पाए जाने के बाद कि पर्याप्त सामग्री है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पुलिस अधीक्षक, भोजपुर की सिफारिश प्रपत्र संख्या 4460 दिनांक 25.06.2021 के आधार पर, ज्ञापंक संख्या 1708 दिनांक 08.07.2021 का बर्खास्तगी का प्रश्नगत आदेश पारित किया। बिहार सी सी ए नियम, 2005 के नियम 20 के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया

याचिकाकर्ता के मामले में विशेष परिस्थितियों में लागू की गई थी, जो सरकारी हित में आवश्यक थी और यह भी कि जांच करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता पूरे कार्यवाही में फरार रहा। इन पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ज्ञापन संख्या 1708 दिनांक 08.07.2021 में निहित प्रश्नगत आदेश और दिनांक 02.11.2022 में निहित अपीलीय आदेश कानून के अनुसार पारित किए गए थे और इस न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका खारिज करने के लिए उपयुक्त है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

8. पक्षकारों को सुना।

9. वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दा यह है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड लगाने से पहले मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह संतुष्टि दर्ज करना कि राज्य के हित में विभागीय जांच आयोजित करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) और बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 20 में निहित प्रावधानों के के अनुरूप है अथवा नहीं?

10. इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ूँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) और बिहार सी सी ए नियम, 2005 के नियम 20 में जहां उन मामलों में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) और बिहार सी सी ए नियम, 2005 के नियम 17 और 19 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होता है। मुझे उपयुक्त प्रतीत होता संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) में निहित प्रावधान को उद्धृत किया जाए:

"311. संघ या किसी राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों को बर्खास्त करना, निष्कासन या उनके पद में कमी करना -

(2) उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त या निष्कासन या पदावन्नती नहीं किया जाएगा, सिवाय उस जांच के जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच के बाद उस पर ऐसा कोई जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, वहां ऐसा जुर्माना ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर लगाया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगाः

बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा ---

(ख) जहां किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से पदावन्नती के लिए अधिकृत प्राधिकारी यह संतुष्टी हो जाए कि किसी कारणवश, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा , ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

11. उपरोक्त खंड यह स्पष्ट करता है कि कारण के बारे में लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करने की जिम्मेदारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर है, की क्यो ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा जहां प्राधिकरण को किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान इसे अनिवार्य बनाता है कि यदि विभागीय जांच को स्थगित करना अपरिहार्य हो, तो अनुशासनात्मक जांच के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना चाहिए क्योंकि विभागीय जांच के बिना सेवा से हटाने, बर्खास्त करने अथवा पदावनति का आदेश संबंधित व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव डालता है। अभिलिखित कारण को उपस्थित परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो प्राधिकरण के लिए दंड लगाने से पहले जांच करना उचित रूप से अव्यवहारिक बनाता है।

12. मुझे नियम 16,17 और विशेष रूप से नियम 20 में निहित प्रावधान पर ध्यान देना भी उचित लगता है, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

16. कार्यवाहियों को स्थापित करने का अधिकार।

(1) सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण या कोई भी प्राधिकरण जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकरण है या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण-

(क) किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है;

(ख) किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है, जिस पर वह अनुशासनात्मक प्राधिकरण इन नियमों के तहत नियम 14 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम है।

(2) एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण, जो इन नियमों के तहत नियम 14 के खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम है, किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नियम 14 के खंड [(vi) से (xi)] [अधिसूचना संख्या 3/एम-166/2006-केए-2797, दिनांक 20.8.2007 द्वारा प्रतिस्थापित] में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है, बावजूद इसके कि ऐसा अनुशासनात्मक प्राधिकरण इन नियमों के तहत नियम 14 खंड (vi) से (xi) के तहत किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम नहीं है। [अधिसूचना संख्या 3/एम-166/2006-का-2797, दिनांक 20.8.2007] द्वारा प्रतिस्थापित।

17. प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया।

(1) नियम 14 के खंड [(vi) से (xi)] [अधिसूचना संख्या 3/एम-166/2006-के. ए.-2797, दिनांक 20.8.2007 द्वारा प्रतिस्थापित] में निर्दिष्ट दंडों में से किसी को भी लागू करने का कोई आदेश इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से, जहां तक हो सके, जांच किए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ कहीं भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सच्चाई के बारे में जाँच करने के लिए आधार हैं, वह स्वयं इसकी जांच कर सकता है, या इन नियमों के तहत इसकी सच्चाई के बारे में जाँच करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है। स्पष्टीकरण। - जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जाँच करता है, वहाँ इस नियम के

उप-नियम (7) से उप-नियम (20) और उप-नियम (22) में जाँच करने वाले प्राधिकारी के लिए किसी भी संदर्भ का अर्थ अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में किया जाएगा।

(3) जहां इस नियम के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी तैयार करेगा या तैयार कराएगा -

(i) दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का सार एक निश्चित और विशिष्ट आरोप के रूप में;

(ii) प्रत्येक आरोप के समर्थन में दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का बयान, जिसमें शामिल होंगे -

(क) सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई किसी भी स्वीकारोक्ति या स्वीकारोक्ति सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों का एक बयान;

(ख) ऐसे दस्तावेजों की एक सूची जिसके द्वारा और ऐसे गवाहों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप-पत्र बनाए रखने का प्रस्ताव है।

(4) अनुशासनात्मक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को आरोप के लेखों की एक प्रति, कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का ऐसा बयान और दस्तावेजों और गवाहों की एक सूची प्रदान करेगा जिसके द्वारा प्रत्येक आरोप के लेख को बनाए रखने का प्रस्ताव है और सरकारी कर्मचारी से, ऐसे समय के भीतर, जो निर्दिष्ट किया जा सके, अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करने और यह बताने की अपेक्षा करेगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

(5) (क) बचाव पक्ष का लिखित बयान प्राप्त होने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं ऐसे आरोप-पत्रों की जांच कर सकता है जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, या यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के तहत नियुक्त करना आवश्यक समझता है, तो वह इस उद्देश्य के लिए एक जांच प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है और जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने बचाव के लिखित बयान में सभी आरोप स्वीकार किए गए हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को ऐसे साक्ष्य लेने के बाद दर्ज करेगा जो वह उचित समझे और नियम 18 में निर्धारित तरीके से कार्रवाई करेगा।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा बचाव का कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण स्वयं आरोप के लेखों की जांच कर सकता है या यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के तहत इस उद्देश्य के लिए एक जांच प्राधिकरण नियुक्त करना आवश्यक समझता है, तो वह ऐसा कर सकता है।

(ग) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण स्वयं किसी आरोप की जांच करता है या ऐसे आरोप के बारे में जांच करने के लिए एक जाँच प्राधिकरण नियुक्त करता है, वह एक आदेश द्वारा, एक सरकारी कर्मचारी या एक कानूनी व्यवसायी को "प्रस्तुत करने वाले अधिकारी" के रूप में नियुक्त कर सकता है। जो आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में उनकी ओर से मामला प्रस्तुत करें।

(6) अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जहां वह जांच करने वाला प्राधिकारी नहीं है, निम्नलिखित अभिलेखों को जांच करने वाले प्राधिकारी को भेजेगा- (i) आरोप-पत्र की एक प्रति और दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का कथन; (ii) सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत बचाव के लिखित बयान, यदि कोई हो, की एक प्रतिः(iii) इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट गवाहों के बयान की एक प्रति, यदि कोई हो। ((iv) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी कर्मचारी को देने का सबूत; और (v) "प्रस्तुत करने वाले अधिकारी" की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति।

(7) सरकारी कर्मचारी अपने द्वारा आरोप के लेखों और दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के बयान की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर ऐसे दिन और ऐसे समय पर जाँचकर्ताप्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा, जैसा कि जाँचकर्ता प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, दस दिनों से अधिक नहीं, जो जाँचकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(8) (क) सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी भी कार्यालय में या तो अपने मुख्यालय में या उस स्थान पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है जहाँ जांच की जानी है। बशर्ते कि वह इस उद्देश्य के लिए किसी कानूनी व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकता है, जब तक कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा

नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एक कानूनी व्यवसायी या अनुशासनात्मक प्राधिकरण न हो, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार अनुमति देता हैः बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी किसी अन्य स्टेशन पर तैनात किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है, यदि जाँचकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति देता हैः बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी ऐसे किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा जिसके पास तीन लंबित अनुशासनात्मक मामले हैं जिनमें उसे सहायता देनी है।

(ख) सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है, बशर्ते ऐसी शर्तें जो सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या इस संबंध में विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

(9) यदि सरकारी कर्मचारी, जिसने अपने बचाव के लिखित बयान में किसी भी आरोप के लेख को स्वीकार नहीं किया है या बचाव में कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया है। जाँचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है, ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे अपने बचाव के लिए कुछ कहना है और यदि वह किसी भी आरोप के लिए दोष स्वीकार करता है, तो जाँचकर्ताप्राधिकारी स्वीकारोक्ति को दर्ज करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(10) जाँचकर्ता प्राधिकारी उन आरोप-पत्रों के संबंध में अपराध का निष्कर्ष वापस करेगा जिन पर सरकारी कर्मचारी अपराध स्वीकार करता है।

(11) यदि सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है या अभिवचन करने से इनकार करता है या चूक करता है, तो जाँचकर्ता प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से वह साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा जिसके द्वारा वह आरोप के लेखों को साबित करने का प्रस्ताव करता है, और एक आदेश दर्ज करने के बाद मामले को तारीख जो तीस दिनों से अधिक की न हो तक के लिए स्थगित कर देगा यह दर्ज़ करते हुये कि सरकारी कर्मचारी अपना बचाव तैयार करने के उद्देश्य से -

(i) निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण करें, आदेश के पाँच दिनों के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो पाँच दिनों से अधिक न हो जिसे जाँचकर्ताप्राधिकारी उपनियम (3) में सूची में की अनुमति दे सकता है;

(ii) उसकी ओर से जाँच किए जाने वाले गवाहों की सूची प्रस्तुत करें; ध्यान दें:-यदि सरकारी कर्मचारी उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित गवाहों के बयानों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए लिखित रूप में आवेदन करता है, तो जाँचकर्ता प्राधिकारी उसे जल्द से जल्द ऐसी प्रतियां प्रदान करेगा।

(iii) आदेश के दस दिनों के भीतर या जाँचकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमत की गई किसी भी और अवधि के भीतर, सरकार के कब्जे में हैं लेकिन इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं हैं किसी भी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुति के लिए नोटिस देना होगाः बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा खोजे जाने या पेश किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना होगा।

(12) जाँचकर्ताप्राधिकारी, दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुत करने के लिए सूचना प्राप्त होने पर, उसी या उनकी प्रतियों को उस प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं, ऐसी तारीख तक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग के साथ, जो ऐसी मांग में निर्दिष्ट की जा सकती हैःबशर्ते कि जाँचकर्ताप्राधिकारी, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे दस्तावेजों की मांग करने से इनकार कर सकता है जो उसकी राय में मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

(13) इस नियम के उप-नियम(12) के अनुसार निर्दिष्ट मांग की प्राप्ति पर। अपेक्षित दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जा रखने वाला प्रत्येक प्राधिकारी उन्हें जाँचकर्ताप्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगाःबशर्ते कि अधिगृहीत दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जा रखने वाले प्राधिकरण का, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या किसी भी दस्तावेज का प्रस्तुत करना राज्य के लोक हित या सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो वह तदनुसार जाँचकर्ता प्राधिकरण को सूचित करेगा और जाँचकर्ताप्राधिकरण, इस तरह सूचित

होने पर, सरकारी कर्मचारी को जानकारी देगा और ऐसे दस्तावेजों को पेश करने या खोजने के लिए उसके द्वारा की गई माँग को वापस ले लेगा।

(14) जाँच के लिए निर्धारित तिथि पर, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जिसके द्वारा आरोप के लेखों को साबित करने का प्रस्ताव है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से गवाहों से पूछताछ की जाएगी और सरकारी कर्मचारी द्वारा या उनकी ओर से उनसे जिरह की जा सकती है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को उन किसी भी बिंदु पर गवाहों से फिर से पूछताछ करने का अधिकार होगा, जिन पर उनसे जिरह की गई है,लेकिन जाँचकर्ता प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी नए मामले पर नहीं। जाँचकर्ता प्राधिकारी भी गवाहों से ऐसे सवाल कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(15) यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से मामला समाप्त होने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है, तो जांच प्राधिकारी, अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सरकारी कर्मचारी को दी गई सूची में शामिल नहीं किए गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है या स्वयं नए साक्ष्य की मांग कर सकता है या किसी गवाह को वापस बुला सकता है और उससे फिर से पूछताछ कर सकता है और ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारी को, यदि वह इसकी मांग करता है, तो प्रस्तावित साक्ष्य की सूची की एक प्रति रखने और ऐसे नए साक्ष्य को प्रस्तुत करने से पहले तीन स्पष्ट दिनों के लिए जांच को स्थगित करने का अधिकार होगा, स्थगन के दिन और उस दिन को छोड़कर जिस दिन जांच की जाती है। जाँचकर्ता प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेने से पहले उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा। जाँचकर्ता प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अनुमति दे सकता है, यदि उसकी राय है कि न्याय के हित में इस तरह के साक्ष्य का उत्पादन आवश्यक हैःबशर्ते कि नए साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी गवाह को साक्ष्य के पूरक के रूप में वापस नहीं बुलाया जाएगा। यदि मूल रूप से प्रस्तुत साक्ष्य में कोई अंतर्निहित कमी या दोष है तो इस तरह के साक्ष्य की मांग की जा सकती है।

(16) अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा मामले की कार्यवाही समाप्ती पर , सरकारी कर्मचारी के द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपना बचाव बताने की आवश्यकता होगी, जो वह चाहे। यदि बचाव मौखिक रूप से किया जाता है, तो इसे दर्ज किया जाएगा और सरकारी कर्मचारी को रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। दोनों ही मामलों में, बचाव के बयान की एक प्रति, यदि कोई हो, नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को दी जाएगी।

(17) इसके बाद सरकारी कर्मचारी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी चाहे तो अपनी ओर से स्वयं का परीक्षणकर सकता है। सरकारी कर्मचारी द्वारा पेश किए गए गवाहों से तब पूछताछ की जाएगी और वे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए गवाहों पर लागू प्रावधानों के अनुसार पूछताछ करने वाले प्राधिकारी द्वारा परीक्षण, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(18) जाँच अधिकारी, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपना मामला बंद करने के बाद, और यदि सरकारी कर्मचारी ने स्वयं की जाँच नहीं की है, तो आम तौर पर सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों पर उससे पूछताछ कर सकता है।

(19) जाँचकर्ता प्राधिकारी, साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूरा होने के बाद, नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और सरकारी कर्मचारी को सुन सकता है, या यदि वे चाहें तो उन्हें अपने-अपने मामले की लिखित जानकारी दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(20) यदि सरकारी कर्मचारी जिसे प्रभार के लेखों की एक प्रति दी गई है, वह इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता है या जाँचकर्ता प्राधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है या अन्यथा इस नियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है या इनकार करता है, तो जाँचकर्ता प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकता है।

(21) (क) जहां नियम 14 के खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम कोई अनुशासनात्मक प्राधिकरण [लेकिन खंड

[(vi) से (xi) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम नहीं है] [नियम 14 के अधिसूचना संख्या 3/एम-166/2006-केए-2797, दिनांक 20.8.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।], ने स्वयं किसी आरोप की जांच की है या उससे जाँचकराई है और उस प्राधिकरण ने अपने स्वयं के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी जाँचकर्ता प्राधिकरण के किसी भी निष्कर्ष पर अपने निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि खंड [(vi) से (xi)] [अधिसूचना संख्या 3/एम-166/2006-का-2797, दिनांक 20.8.2007 द्वारा प्रतिस्थापित] में निर्दिष्ट दंड सरकारी कर्मचारी पर लगाए जाने चाहिए, तो वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख को नियम 14 का खंड [(vi) से (xi)] [नियम 14 का अधिसूचना संख्या 3/एम-166/2006-केए-2797, दिनांक 20.8.2007 द्वारा प्रतिस्थापित] में उल्लिखित दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम ऐसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजेगा।

(ख) जिस अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अभिलेख इस प्रकार भेजे जाते हैं, वह अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर कार्य कर सकता है या यदि उसकी राय है कि न्याय के हित में किसी भी गवाह की आगे की परीक्षण आवश्यक है, तो गवाहों को वापस बुला सकता है और गवाहों की परीक्षण, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षण कर सकता है और सरकारी कर्मचारी पर ऐसे दंड लगा सकता है जो वह इन नियमों के अनुसार उचित समझे।

(22) जब भी कोई जाँचकर्ता प्राधिकारी, किसी जांच में साक्ष्य के पूरे या किसी हिस्से को सुनने और दर्ज करने के बाद, उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर देता है, और उसके बाद कोई अन्य जाँचकर्ताप्राधिकारी आता है, जिसके पास ऐसी अधिकारिता होती है, तो इस तरह का उत्तराधिकारी प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस तरह से दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा आंशिक रूप से दर्ज किए गए और आंशिक रूप से स्वयं द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर कार्य कर सकता हैः बशर्ते कि यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की राय है कि किसी भी गवाह की आगे की जांच, जिसका साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है, न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसे किसी भी गवाह को वापस बुला सकता है, परीक्षण कर सकता है, जिरह कर सकता है और पुनः परीक्षण कर सकता है जैसा कि पहले प्रावधान किया गया है।

(23) (I) जाँच के समापन के बाद, एक अभिलेख तैयार किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(क) आरोप के लेख और दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का बयान;

(ख) आरोप की प्रत्येक वस्तु के संबंध में सरकारी सेवक का बचाव।

(ग) प्रत्येक आरोप-पत्र के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन,

(घ) आरोप के प्रत्येक लेख पर निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण- यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही आरोप के मूल लेखों से अलग कोई आरोप लेख स्थापित कर सकती है, तो वह आरोप के ऐसे लेख पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता हैः बशर्ते कि ऐसे आरोप के लेख पर निष्कर्ष तब तक दर्ज नहीं किए जाएंगे जब तक कि सरकारी कर्मचारी ने या तो उन तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है जिन पर ऐसा आरोप का लेख आधारित है या उसे के ऐसे आरोप के खिलाफ अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिला है।

(ii) जांच प्राधिकारी, जहां वह स्वयं अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच के अभिलेख भेजेगा जिसमें शामिल होंगे-

(क) इस उप नियम के खंड (i) के तहत उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत बचाव का लिखित बयान, यदि कोई हो;

(ग) जाँच के दौरान प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या सरकारी कर्मचारी या दोनों द्वारा दायर लिखित विवरण, यदि कोई हो; और

(ङ) जाँच के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी और जाँच प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश, यदि कोई हों।

20. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया।

- नियम 17 से 19 (i) में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

(i)जहां किसी सरकारी कर्मचारी पर आचरण के आधार पर कोई दंड लगाया जाता है, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है, या

(ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए और इसका कारण वह लिखित रूप में दर्ज करें कि इन नियमों में दिए गए तरीके से जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, या

(iii) जहां सरकार को यह समाधान हो जाता है कि राज्य के हित में इन नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझेः बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी को खंड (i) के तहत किसी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सकता हैः बशर्ते यह भी कि इस नियम के तहत किसी भी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा, जहां इस तरह का परामर्श आवश्यक है।

13. मामले के तथ्य में, मुझे लगता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने नियमित विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ना अनुचित नहीं पाया है, जबकि इस प्रक्रिया में साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक था कि अनाधिकृत अनुपस्थिति जानबूझकर की गई थी या नहीं। 18/36 परंतु, बिना इस तथ्य को स्थापित किए कि अनधिकृत अनुपस्थिति जानबूझकर थी और इसके परिस्थितियों पर विचार किए बिना केवल पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के पत्र संख्या 4460 में निहित 25.06.2021 की सिफारिश के आधार यह निष्कर्ष निकाला गया कि जांच अव्यावहारिक थी। याचिकाकर्ता के मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकरण डी. आई. जी. है और अभिलेखों से, जिसे न्यायालय में पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा पढ़ा गया है, केवल यह दर्शाता है कि पुलिस अधीक्षक, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, ने केवल यह दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा छुट्टी के लिए कोई आवेदन या पूर्व अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई थी और वह

जानबूझकर अनुपस्थित रहा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण, डी. आई. जी. ने नोट किया कि उन्होंने उन बाध्यकारी परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए स्वयं विचार नहीं किया है जिनके तहत याचिकाकर्ता के लिए रिपोर्ट करना या कर्तव्य का पालन करना संभव नहीं था और यह कदाचार के बराबर होगा। ऐसी ही परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कृष्णकांत बी. परमार बनाम भारत संघ एवं अन्य*** के मामले में जिसे ***(2012) 3 एस. सी. सी. 178*** में रिपोर्ट किया। जिसमे पैरा संख्या 17, 18 और 19, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः-

> *"17.यदि अनुपस्थिति बाध्यकारी परिस्थितियों का परिणाम है जिसके तहत रिपोर्ट करना या कर्तव्य का पालन करना संभव नहीं था, तो ऐसी अनुपस्थिति को जानबूझकर नहीं माना जा सकता है। बिना किसी आवेदन या पूर्व अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थिति अनधिकृत अनुपस्थिति के बराबर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब हमेशा जानबूझकर नहीं होता है। ऐसी अलग-अलग संभावनाएँ हो सकती हैं जिनके कारण एक कर्मचारी कर्तव्य से दूर रह सकता है, जिसमें उसके नियंत्रण से परे मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ जैसे बीमारी, दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होना आदि शामिल हैं, लेकिन ऐसे मामले में कर्मचारी को कर्तव्य के प्रति समर्पण या सरकारी कर्मचारी के अनुचित व्यवहार की विफलता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।*
>
> *18.एक विभागीय कार्यवाही में, यदि कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप लगाया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि अनुपस्थिति जानबूझकर है, इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, अनुपस्थिति कदाचार के बराबर नहीं होगी।*
>
> *19. वर्तमान मामले में साक्ष्य की मूल्यांकन पर जांच अधिकारी ने हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित था, लेकिन यह अभिनिर्धारित करने में विफल रहा कि अनुपस्थिति जानबूझकर थी; अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी इसकी सराहना करने में विफल रहे और अपीलार्थी को गलत तरीके से दोषी ठहराया।*

14. सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में निर्धारित कानून का विश्लेषण करते हुए ***(2016) 8 एस. सी. सी. 471*** में रिपोर्ट किए गए ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ*** के मामले में विभागीय जांच के आयोजन में अलग-अलग स्थिति का सारांश दियाः,उक्त निर्णय के अनुच्छेद संख्या 34,35,36,37 और 38 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> ***34.*** *इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र और पूर्व आपराधिक वृत्तका सत्यापन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और नियोक्ता के लिए पदधारी के पूर्व आपराधिक वृत्त का निर्णय करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।*
>
> ***35.*** *"महत्वपूर्ण" जानकारी को छिपाने से यह अनुमान लगाया जाता है कि जिसे छुपाया जाता है वह हर तकनीकी या तुच्छ जानकारी मामले में "मायने" नहीं रखता है। नियोक्ता को उम्मीदवारी रद्द करने या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों/निर्देशों, यदि कोई हो, पर उचित विचार करते हुए कार्य करना होगा। यद्यपि एक व्यक्ति जिसने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है और मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।*
>
> ***36.*** *किस मानदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है, उच्च पद में सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे, न कि केवल समान सेवा के लिए। निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कर्तव्यों/सेवाओं और शक्तियों के पद/प्रकृति का उपयोग विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर किया जाना चाहिए।*
>
> ***37.*** *"मैकार्थीवाद" संवैधानिक लक्ष्य के विपरीत है, उपयुक्त मामलों में युवा अपराधियों को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए, सुधारवादी*

सिद्धांत की परस्पर क्रिया को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे समान्य तौर पर लागू किया जा सकता है, लेकिन उम्मीदवारी को रद्द करने या किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है।

38. *हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैं:*

38.1.*एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।*

38.2.*गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।*

38.3.*नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।*

38.4.*यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का तथ्य छुपाया गया हैया झूठी जानकारी दी गयी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:*

38.4.1.*तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य को छिपाने या गलत जानकारी देने की चूक को क्षमा करते हुए उसे को नजरअंदाज कर सकता है।*

38.4.2.*जहां ऐसे मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है,जो तुच्छ प्रकृति का नहीं नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।*

38.4.3.*यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्व आपराधिक वृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।*

38.5. *ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने ईमानदारी से एक समाप्त आपराधिक मामले का तथ्य भी घोषित किया है। नियोक्ता को अभी भी पूर्व आपराधिक वृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।*

38.6.*यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।*

38.7.*कई लंबित मामलों के संबंध में जानबूझकर तथ्य को छुपाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।*

38.8. *यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।*

38.9.*यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो तथ्य को छिपाने या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।*

38.10. *तथ्य को छिपाने या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी*

नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो फिटनेस के सवाल को संबोधित करते समय वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में तथ्य को छिपानेया गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11. *इससे पहले कि किसी व्यक्ति को सत्य को छिपाने या झूठा सुझाव देने का दोषी ठहराया जाए, उस तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।*

15. अब, निर्धारित करने का प्रश्न यह है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि के अभाव में, उस याचिकाकर्ता के विरुद्ध, जिसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को अनुसंधान अधिकारी द्वारा सहार थाना कांड संख्या.- 123/2021 दिनांक 06.06.2021, में अनुसंधानकर्ता द्वारा दायर अंतिम प्रपत्र के आधार पर समाप्त कर दिया गया है, सेवा से बर्खास्तगी का आदेश में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है? हस्तक्षेप किया मुझे लगता है कि उस मापदंड पर चर्चा करना उचित है, जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के मामले में नियम 20 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है। इसी तरह के प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा ***भारत संघ एवं अन्य बनाम तुलसीराम पटेल, (1985) 3 एस. सी. सी. 398*** में विचार किया गया था। इस प्रश्न का निर्णय अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधानों के संदर्भ में किया गया था, जो हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं- जिसके प्रावधान नियमों के समानार्थी हैं। *तुलसीराम पटेल (उपरोक्त)* में निम्नलिखित शब्दों में प्राकृतिक न्याय के अपवर्जन के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की वैधता के बारे में विचार किया गया हैः

"106. इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है। अनुच्छेद 309 के प्रारंभिक शब्द उस अनुच्छेद को स्पष्ट रूप से "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" बनाते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत या उस अनुच्छेद के लिए संदर्भित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों को संविधान

के प्रावधानों के अधीन बनाया जाना चाहिए, यदि वे वैध हैं। अनुच्छेद 310 (1) जो प्रसादपर्यंत के सिद्धांत का प्रतीक है, संविधान में निहित एक प्रावधान है। इसलिए, अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत या उस अनुच्छेद के लिए संदर्भित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम अनुच्छेद 310 (1) के अधीन हैं। अनुच्छेद 310 (1) के शुरुआती शब्दों से उसमें निहित प्रसादपर्यंत का सिद्धांत "इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर" संचालित होता है। अनुच्छेद 311 संविधान का एक स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए, अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत या अनुच्छेद 309 के लिए संदर्भित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम अनुच्छेद 310 (1) और अनुच्छेद 311 दोनों के अधीन होंगे। इस स्थिति को जे. सुब्बा राव ने मोती राम डेका मामले [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 600: (1964) 5 एससीआर 683,734-5:(1964) 2 एल. एल. जे. 467] पी.734 में अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में इंगित किया था। अनुच्छेद 309 के तहत नियम प्रसादपर्यंत के सिद्धांत के अधीन हैं और प्रसादपर्यंत का सिद्धांत स्वयं अनुच्छेद 311 द्वारा उस पर लगाई गई दो सीमाओं के अधीन है। इस प्रकार, जैसा कि उस मामले में बताया गया है, कोई भी नियम जो अनुच्छेद 311 के खंड (1) या खंड (2) का उल्लंघन करता है, अमान्य होगा। हालाँकि, जहाँ दूसरा परंतुक लागू होता है, वहाँ राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल प्रसादपर्यंत का सिद्धांत के प्रयोग पर एकमात्र प्रतिबंध अनुच्छेद 311 के खंड (1) में निहित है। किसी अधिनियम या नियम के लिए यह उपबंध करना कि उस मामले में जहां दूसरा परंतुक लागू होता है, उस परंतुक द्वारा अपवर्जित कोई भी सुरक्षा उपाय किसी सरकारी कर्मचारी के लिए उपलब्ध होगा, ऐसे अधिनियम या नियम के बराबर होगा जो पर लागू होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत का सिद्धांत, जैसा भी मामला हो, असंवैधानिक होने के कारण अमान्य होगी। हालाँकि, यह कानूनों के निर्माण का एक सुव्यवस्थित नियम है कि जहाँ दो व्याख्याएँ संभव हैं, जिनमें से एक विशेष वैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता को संरक्षित और सुरक्षित रखेगी, जबकि दूसरी इसे असंवैधानिक और शून्य बना देगी, एक जो अपनी संवैधानिकता को बचाता है और संरक्षित करता है, उसे अपनाया जाना चाहिए और दूसरा खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की संवैधानिकता को उस वैधानिक प्रावधान को निर्देशिका के रूप में व्याख्या करके संरक्षित किया जा सकता है न कि अनिवार्य के रूप में। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक वैधानिक प्रावधान निर्देशिका है, अदालतें प्रदर्शन को मजबूर करने या इस तरह के प्रावधान द्वारा बनाए गए कर्तव्य के उल्लंघन को दंडित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और इस तरह के प्रावधान की अवज्ञा में कोई अयोग्यता नहीं होगी- कानून पर संदेह, सातवीं संस्करण, पृष्ट 229 देखें. ऐसे मामले में इस तरह के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किसी सरकारी कर्मचारी को कार्रवाई का कोई

कारण या चुनौती का आधार प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि कार्रवाई का ऐसा कारण या चुनौती का आधार अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक द्वारा वर्जित होगा। अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 310 (1) और अनुच्छेद 311 दोनों के अधीन होगा। इस स्थिति को जे. सुब्बा राव ने मोती राम डेका मामले [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 600: 1964) 5 एससीआर 683,734-5:(1964) 2 एल. एल. जे. 467]पृष्ट 734, में अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में इंगित किया था। (अनुच्छेद 309 के तहत नियम प्रसादपर्यंत के सिद्धांत के अधीन हैं और प्रसादपर्यंत के सिद्धांत स्वयं अनुच्छेद 311 द्वारा उस पर लगाई गई दो सीमाओं के अधीन है। इस प्रकार, जैसा कि उस मामले में बताया गया है, कोई भी नियम जो अनुच्छेद 311 के खंड (1) या खंड (2) का उल्लंघन करता है, अमान्य होगा। हालाँकि, जहाँ दूसरा परंतुक लागू होता है, वहाँ राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की प्रसादपर्यंत का सिद्धांत के प्रयोग पर एकमात्र प्रतिबंध अनुच्छेद 311 के खंड (1) में निहित है। किसी अधिनियम या नियम के लिए यह उपबंध करना कि उस मामले में जहां दूसरा परंतुक लागू होता है, उस परंतुक द्वारा अपवर्जित कोई भी सुरक्षा उपाय किसी सरकारी कर्मचारी के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा अधिनियम या नियम होगा जो राष्ट्रपति या राज्यपाल की प्रसादपर्यंत का सिद्धांत को बाधित करता है, और असंवैधानिक होने के कारण अमान्य होगा। हालाँकि, यह कानूनों के निर्माण का एक सुव्यवस्थित नियम है कि जहाँ दो व्याख्याएँ संभव हैं, जिनमें से एक विशेष वैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता को संरक्षित और सुरक्षित रखेगी, जबकि दूसरी इसे असंवैधानिक और शून्य बना देगी, एक जो अपनी संवैधानिकता को बचाता है और संरक्षित करता है, उसे अपनाया जाना चाहिए और दूसरे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की संवैधानिकता को उस वैधानिक प्रावधान को निर्देशिका के रूप में व्याख्या करके संरक्षित किया जा सकता है न कि अनिवार्य। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक वैधानिक प्रावधान निर्देशिका है, अदालतें प्रदर्शन को मजबूर करने या इस तरह के प्रावधान द्वारा बनाए गए कर्तव्य के उल्लंघन को दंडित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और इस तरह के प्रावधान की अवज्ञा में कोई अयोग्यता नहीं होगी- कानून पर संदेह, सातवीं संस्करण, पृष्ट 229 देखें. ऐसे मामले में इस तरह के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किसी सरकारी कर्मचारी को कार्रवाई का कोई कारण या चुनौती का आधार प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि कार्रवाई का ऐसा कारण या चुनौती का आधार अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक द्वारा वर्जित होगा।

16. इसलिए, यह संवैधानिक योजना के अनुसार है कि सेवा संबंधी ऐसे नियम, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपवर्जित करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के प्रतिबिंब होने चाहिए।

17. जिन मानदंडों पर संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के खंड (बी) के तहत जांच करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन्हें *तुलसीराम पटेल (उपरोक्त)* मामले में संविधान पीठ द्वारा विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय में यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः

> *"130.खंड (बी) के आवेदन के लिए पूर्ववर्ती शर्त अनुशासनात्मक प्राधिकरण की संतुष्टि है कि अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा अनुध्यात जांच "करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है"। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपयोग किए गए शब्द "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं हैं" और "अव्यवहारिक" नहीं हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार "व्यवहार्य" का अर्थ है "व्यवहार में लाने में सक्षम, कार्रवाई में निष्पादित, प्रभावित, सिद्ध या किया गया; व्यवहार्य"। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी "व्यावहारिक" शब्द को अन्य बातों के साथ परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "अभ्यास या प्रदर्शन करना संभवः व्यवहार में लाने, करने या पूरा करने में सक्षमः संभव है"। इसके अलावा, उपयोग किए गए शब्द "व्यावहारिक नहीं" हैं, लेकिन "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं" हैं। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी "यथोचित" शब्द को उचित तरीके से परिभाषित करती हैःकाफी हद तक "। इस प्रकार, जाँच करना व्यवहार्य था या नहीं, इसका निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि ऐसा करना उचित रूप से व्यवहार्य था या नहीं। यह कुल या पूर्ण अव्यवहारिकता नहीं है जो खंड (बी) द्वारा आवश्यक है। आवश्यक बात यह है कि मौजूदा स्थिति को उचित दृष्टिकोण से देखने वाले एक समझदार व्यक्ति की राय में जांच का आयोजन व्यावहारिक नहीं है। उन मामलों की गणना करना संभव नहीं है जिनमें जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन कुछ उदाहरण दृष्टांत के रूप में दिए जा सकते हैं। जहां सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से अपने सहयोगियों के माध्यम से या उनके साथ मिलकर, उन गवाहों को डराता है, धमकी देता है या डराता है जो प्रतिशोध के डर से अपने खिलाफ सबूत देने जा रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके या जहां सरकारी कर्मचारी खुद*

या दूसरों के साथ या उनके माध्यम से अनुशासनात्मक अधिकारी या अपने परिवार के सदस्यों को धमकी देता है, डराता है और आतंकित करता है ताकि वह जांच करने या उसे आयोजित करने का निर्देश देने से डरता हो। जहां हिंसा का माहौल है या सामान्य जांच आयोजित करना भी उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। अनुशासनहीनता और अवज्ञा प्रबल है, और यह मायने नहीं रखता कि संबंधित सरकारी कर्मचारी इस तरह का माहौल बनाने में पक्षकार है या नहीं। इस संबंध में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संख्याएँ मजबूर करती हैं और भयभीत करती हैं जबकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। जाँच आयोजित करने की उचित व्यावहारिकता अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन का विषय है। इस तरह के अधिकारी आम तौर पर मौके पर होते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण इसका सबसे अच्छा न्यायाधीश है जो अनुच्छेद 311 का खंड (3) इस प्रश्न पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय को अंतिम बनाता है। एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अनुशासनात्मक जांच को हल्के में या मनमाने ढंग से या गलत उद्देश्यों से या केवल जांच से बचने के लिए या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभाग का मामला कमजोर होने के कारण विफल होने की उम्मीद नहीं की जाती है। जहां तक न्यायिक समीक्षा की अदालत की शक्ति का संबंध है, अनुच्छेद 311 (3) द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय को दी गई अंतिमता अदालत पर बाध्यकारी नहीं है और ऐसे मामले में अदालत जांच के साथ-साथ जुर्माना लगाने के आदेश को भी रद्द कर देगी। अर्जुन चौबे बनाम भारत संघ [(1984) 2 एस. सी. सी. 578 का मामला एक उदाहरण है। उस मामले में, अपीलार्थी मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे, वाराणसी के कार्यालय में एक वरिष्ठ क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी ने अपीलार्थी को एक पत्र लिखकर उनसे उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक से संबंधित घोर अनुशासनहीनता के बारह आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया। अपीलार्थी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और अगले ही दिन उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक ने अपीलार्थी को यह कहते हुए दूसरा नोटिस दिया कि उसका स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं था और उसे उन आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का एक और मौका दिया जा रहा था। अपीलार्थी ने अपना आगे का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया लेकिन अगले ही दिन उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक ने उन्हें इस आधार पर बर्खास्त करने का आदेश पारित किया कि वह सेवा में बनाए रखने के योग्य नहीं थे। इस न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि

उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के साथ अपीलार्थी के आचरण से संबंधित बारह में से सात आरोप जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे और यदि जांच की जानी थी, तो विभाग के लिए प्रमुख गवाह स्वयं उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक होता, जिसके परिणामस्वरूप वही व्यक्ति मुख्य आरोपकर्ता, मुख्य गवाह और मामले का न्यायाधीश भी होता।

131. यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि कोई अपराधी सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण को इतना आतंकित करता है कि न तो वह अधिकारी और न ही उस स्थान पर तैनात कोई अन्य अधिकारी जांच करने को तैयार है, तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने के लिए बाहर से भेजा जा सकता है। यह प्रस्तुतिकरण स्वयं दर्शाता है कि ऐसे मामले में जांच का आयोजन उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। यह मानना अतार्किक होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य को लकवाग्रस्त होना होना चाहिए। लकवाग्रस्त होनाक्योंकि एक अपराधी सरकारी कर्मचारी या तो स्वयं या दूसरों के साथ या उनके माध्यम से जांच के आयोजन को उचित रूप से व्यावहारिक नहीं बनाता है।

132. यह आवश्यक नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने से पहले ऐसी स्थिति मौजूद होनी चाहिए जो जांच के आयोजन को उचित रूप से व्यावहारिक नहीं बनाती है। ऐसी स्थिति बाद में जांच के दौरान भी अस्तित्व में आ सकती है, उदाहरण के लिए, सरकारी कर्मचारी पर आरोप पत्र की तामिला के बाद या उसने अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद या आंशिक रूप से साक्ष्य दिए जाने के बाद भी। ऐसे मामले में भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करने का हकदार होगा क्योंकि उस खंड में "जांच" शब्द में जांच का हिस्सा शामिल है। सरकारी कर्मचारी को सुनवाई या आगे की सुनवाई का अवसर देना भी उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, जब जांच शुरू होने पर या लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी फरार हो जाता है और उसे सूचना नहीं दी जा सकती है या वह जांच में भाग नहीं लेगा। ऐसे मामलों में, मामले को एक तरफा और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष सामग्री पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए, जहां जांच का एक हिस्सा आयोजित किया गया है और बाकी खंड (बी) के तहत या उसके अनुरूप सेवा नियमों में एक प्रावधान के साथ वितरित किया गया है, वहां भी दूसरे परंतुक के अपवर्जक शब्द अपने पूरे जोर से काम करते हैं और सरकारी कर्मचारी शिकायत नहीं कर सकता है कि उसे अनुच्छेद 311 (2) द्वारा

प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए बर्खास्त, हटा दिया गया है या रैंक में कम कर दिया गया है।

133. दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत वैध आवेदन के लिए आवश्यक दूसरी शर्त यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि के लिए अपना कारण लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए कि अनुच्छेद 311 (2) द्वारा अनुध्यात जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। यह एक संवैधानिक दायित्व है और यदि ऐसा कारण लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, तो जांच का आदेश और उसके बाद दंड का आदेश अमान्य और असंवैधानिक दोनों होगा।

134. यह स्पष्ट है कि जांच के निरस्त करने के कारण की लिखित अभिलेख जुर्माना लगाने के आदेश से पहले होनी चाहिए। इसलिए, जाँच को रद्द करने के कारण को अंतिम क्रम में जगह देने की आवश्यकता नहीं है। कारण को अलग से दर्ज करना और फिर लगाए जाने वाले जुर्माने के सवाल पर विचार करना और जुर्माना लगाने का आदेश पारित करना सामान्य बात होगी। हालाँकि, अंतिम आदेश में कारण दर्ज करना बेहतर होगा ताकि इस आरोप से बचा जा सके कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले कारण लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे गढ़ा गया था। जाँच को निरस्त करने के कारण में विस्तृत विवरण होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कारण अस्पष्ट या दूसरे परंतुक के खंड (बी) की भाषा का केवल दोहराव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए खंड (बी) की आवश्यकता का केवल यह कहना अनुपालन नहीं होगा कि वह संतुष्ट था कि कोई भी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। कभी-कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि यह उचित रूप से जाँच को समाप्त करने के लिए विस्तृत कारण देना व्यवहार्य नहीं है। जाँच को समाप्त करने के लिए विस्तृत कारण देना व्यवहार्य है। हालाँकि, यह अपने आप में आदेश को अमान्य नहीं करेगा। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष और उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

18. संविधान पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***दक्षिणी रेलवे अधिकारी संघ बनाम भारत संघ और अन्य, (2009) 9 एस. सी. सी. 24*** में रिपोर्ट किए गए मामले में पालन किया गया, इन सिद्धांतों का आगे ***वेद मित्तर गिल बनाम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ और अन्य (2015) 8 एस. सी.***

सी. 86 में रिपोर्ट मामले में और अधिक विस्तृत रूप में स्वीकार किया तथा उनका पालन किया। वेद मित्तर गिल (उपरोक्त) के तथ्यों से पता चलता है कि जब गिल जनवरी, 2004 में पुलिस उपाधीक्षक, मॉडल जेल, बुड़ैल, चंडीगढ़ के रूप में तैनात थे, तो चार विचाराधीन कैदी, जिनमें से तीन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे थे और एक अन्य, एक भूमिगत सुरंग खोदकर मॉडल जेल, बुड़ैल, चंडीगढ़ से भाग निकले। गिल को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करते हुए दिनांक 01.03.2004 के आदेश के माध्यम से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को विभागीय अपीलों को प्राथमिकता देकर दिनांक 01.03.2004 के बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी। उन अपीलों को दिनांकित 11.02.2005 आदेश के अनुसार बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। गिल ने सेवा से उनकी बर्खास्तगी के आदेशों को चुनौती हेतु एक मूल आवेदन के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया। 28/36। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दिनांक 30.01.2006 के आदेश के माध्यम से मूल आवेदन को खारिज कर दिया। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे 01.05.2006 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गिल ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष, गिल द्वारा दायर अपील की सुनवाई स्थानांतरित मामलों के साथ की गई थी, जो जेल में तैनात अन्य अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाएं थीं, जिन्हें इसी तरह बर्खास्त कर दिया गया था और उनकी रिट याचिकाएं अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं जिस समय गिल द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

19. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में *तुलसीराम पटेल* (*उपरोक्त*), **तारसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 13 एस. सी. सी. 581, पंजाब राज्य बनाम हरमन सिंह, (2007) 15 एस. सी. सी. 217** और अन्य उच्च न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान देने के उपरांत माननीय न्यायाधीशगणों ने यह निर्णय दिया कि:

> *"22.अब हम यह निर्धारित करने के लिए प्रश्नगत आदेश की ओर ध्यान देंगे कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दूसरे परंतुक के खंड (बी) के वैध आह्वान के लिए निर्धारित तीन मापदंडों को पूरा किया गया था।*
>
> *23. पहला घटक, जो उपरोक्त खंड (बी) के स्थायी अनुप्रयोग के लिए एक पूर्व शर्त है, यह है कि कथित अपराध ऐसा होना चाहिए जो तीन दंडों में से किसी एक को उचित ठहराए, अर्थात् बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी। हम पहले ही दिनांक 1-3-2004 के आदेश को देख चुके हैं, जिसके तहत अपीलार्थी वेद मित्तर गिल को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अवलोकन से पता चलता है कि सजा विभिन्न खंडों में विभाजित कारणों (विवादित क्रम में दर्ज) पर आधारित थी। पहला पहले पैराग्राफ में निहित है, जो वेद मित्तर गिल को डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मॉडल जेल, बुड़ैल, चंडीगढ़ के रूप में निहित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। दूसरा घटक मॉडल जेल, बुड़ैल, चंडीगढ़ से चार विचाराधीन कैदियों के भागने से संबंधित है। भागने वाले विचाराधीन कैदियों में से तीन पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल थे। इस पैराग्राफ में यह तथ्य भी दर्ज किया गया है कि उक्त तीन विचाराधीन कैदियों के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ संबंध थे। चौथे विचाराधीन कैदी पर हत्या के अपराध के लिए अलग से मुकदमा चलाया जा रहा था। आक्षेपित आदेश का तीसरा घटक, अपीलार्थी/याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई खामियों का मूल्यांकन करने के लिए विचार में ली गई सामग्री से संबंधित है, जो कथित अपराध के संदर्भ में उनकी भागीदारी को प्रकट करेगा, सेवा से बर्खास्तगी के दंड को उचित ठहराएगा।*
>
> *24. अब हम उपरोक्त से उभरने वाली तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले अपीलार्थी वेद मित्तर गिल को सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया था। ऊपर दिए गए पैरा 9 से 11 में उन्हें सौंपे गए स्पष्ट कर्तव्यों का विवरण देने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जेल के सभी कैदियों (सभी कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा) और इसमें उनकी सहायता करने वाले याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अपीलार्थी वेद मित्तर गिल को कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में हर चौबीस घंटे में एक बार खुद को संतुष्ट करना आवश्यक था। वह हर चौबीस घंटे में हर बैरक,*

वार्ड, कोठरी और डिब्बे का दौरा करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध था। उन्हें हर सुबह और शाम को मौजूद रहना था, जब कैदियों को सोने वाले वार्ड या कोठरी या अन्य डिब्बों से बाहर निकाला जाता था, और फिर उसी में वापस लाया जाता था। उन्हें सुबह और रात तक दैनिक रिपोर्ट देनी थी कि सभी कैदी मौजूद हैं और सुरक्षित हिरासत में हैं। उन्हें किसी भी असामान्य घटना के बारे में तुरंत रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता थी। उन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार कपड़ों, बिस्तरों के साथ-साथ अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए कैदियों द्वारा अक्सर आने वाले सभी स्थानों की अच्छी तरह से जांच करने की आवश्यकता थी। और एक रिपोर्ट बनाने के लिए यदि जाँच के दौरान, उसे कोई निषिद्ध वस्तु मिली, हो तो। याचिकाकर्ता अपीलार्थी के साथ जुड़े हुए थे और अपने उपरोक्त कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करते थे। यदि अपीलार्थी वेद मित्तर गिल और याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्यों का लगन से पालन किया होता, तो उक्त संदर्भ की भागने की कोई घटना की कोई संभावना नहीं होती। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि पलायन सुरंग खोदकर पलायन की घटना को ठीक से किया गया था, जिसकी लंबाई 94 फीट (21'' × 21'' के विकर्ण आयामों के साथ) थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छह अलग-अलग कारण व्यक्त किए गए हैं। हमने यहाँ ऊपर, , दिनांकित 1-3-2004 के आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से अवलोकन किया है। यह हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को पूरी तरह से स्थापित करता है।

25. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए दृढ़ संकल्प को जब वेद मित्तर गिल को सौंपे गए कर्तव्यों के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से देखा जाता है, तो इसमें किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, कि सक्षम प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालना उचित ठहराया था कि ऊपर उल्लिखित चार कैदी कभी भी बच नहीं सकते थे, अगर अपीलकर्ता वेद मित्तर गिल और याचिकाकर्ताओं ने उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का लगन से निर्वहन किया होता। इस प्रकार निष्कर्ष निकालने के बाद, अपीलार्थी/याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी और दोषारोपण के बारे में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा पूरी तरह से उचित थी, क्योंकि उनके अपराध के परिणामस्वरूप चार खूंखार कैदी भाग गए थे।

26. दूसरा घटक जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दूसरे परंतुक के खंड (बी) के वैध प्रयोग के लिए पूरा करने की आवश्यकता है, वह है सक्षम प्राधिकारी का संतोष, कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमित विभागीय जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। इस सवाल पर कि क्या जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य था, सक्षम प्राधिकारी ने पैराग्राफ में अपना निष्कर्ष दर्ज किया है, जो अपीलार्थी/याचिकाकर्ताओं की भागीदारी को दर्शाता है। इंगित किए गए कारणों में, यह दर्ज किया गया है कि वेद मित्तर गिल मॉडल जेल, बुडैल, चंडीगढ़ के एक वरिष्ठ, स्थायी और गैर-हस्तांतरणीय अधिकारी

होने के नाते, उनके कनिष्ठ जेल अधिकारी, जो अकेले इस तरह की विभागीय कार्यवाही में गवाह होते, उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आने की संभावना नहीं थी, क्योंकि भविष्य में उनका क्रोध अर्जित होने का डर था। फरार विचाराधीन कैदियों के बब्बर खालसा इंटरनेशनल, एक ज्ञात और खूंखार आतंकवादी संगठन के साथ संबंध भी विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए थे, क्योंकि यह अपीलार्थी/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच करने के लिए एक कारण था। यह आम जानकारी की बात है और इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान देना उचित होगा कि विचाराधीन अवधि के दौरान बड़ी संख्या में आतंकवादियों को इस तथ्य के कारण बरी कर दिया गया कि गवाह डर के कारण उनके खिलाफ गवाही नहीं देते थे, या वैकल्पिक रूप से, जो गवाह अपनी गवाही दर्ज करने के लिए संबंधित अदालतों के समक्ष पेश हुए, वे इसी कारण से मुकर गए।

27. आक्षेपित आदेश में देखे गए तथ्यात्मक विवरण में प्रस्तुत स्थिति स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी के हाथों संतुष्टि के लिए बेंचमार्क प्राप्त करती है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होता।

28. भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दूसरे परंतुक पर खंड (बी) के वैध अनुप्रयोग के लिए तीसरा आवश्यक घटक यह है कि सक्षम प्राधिकारी को उपरोक्त संतुष्टि के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। वर्तमान मामले में, इस मुद्दे पर कोई गंभीर विवाद नहीं है क्योंकि संतुष्टि के कारणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश (दिनांक 1-3-2004) में ही दर्ज किया गया है।

29. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम संतुष्ट हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दूसरे परंतुक के खंड (बी) के वैध/कानूनी आवेदन के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का विधिवत पालन किया गया था।

20. दूसरा मुद्दा जो विचार करने योग्य है वह हैः यदि नियमों के नियम 20 के अंतर्गत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विभागीय जाँच की सामान्य प्रक्रिया को अपनाए बिना कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग नियम के तहत विवेकपूर्ण और वैध था? अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियम 20 के तहत विभागीय जांच को छोड़ने की शक्ति प्राप्त करता है, यदि वह संतुष्ट है कि नियमों के तहत प्रदान किए गए तरीके से जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है और इसकी संतुष्टि के कारणों को दर्ज करता है।

जैसा कि तुलसीराम पटेल (उपरोक्त) में बताया गया है। (ऊपर) कि शब्द *'यथोचित रूप से व्यवहार्य नहीं* एक '*कुल या पूर्ण अव्यावहारिकता'* को अभिनिर्धारित नहीं करते हैं, माननीय न्यायाधीशों के शब्दो में बस इतना ही आवश्यक है कि एक समझदार व्यक्ति की समझ के लिए, परिस्थितियों में जांच का आयोजन अव्यवहारिक प्रतीत होना चाहिए। तुलसीराम पटेल (ऊपर) में एक टिप्पणी है, जो इस सवाल पर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या उचित रूप से व्यवहार्य माना जा सकता है। हालाँकि वहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि,' *जाँच करना व्यवहार्य था या नहीं, इसका निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि ऐसा करना उचित रूप से व्यवहार्य था या नहीं।*

21. *तुलसीराम पटेल (उपर्युक्त*) में निर्धारित कानून की पृष्ठभूमि में, पहले आरोप की गंभीरता पर विचार करना आवश्यक है, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी जैसे बड़े दंड का प्रावधान है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है की एक सह-आरोपी अशोक सिंह के साथ ट्रक चालकों से अवैध रूप से धन एकत्र करने में सुविधा प्रदान करने वाले कार्य में पक्षकार होने के बारे में है। इस प्रकार एकत्र की गई कुल राशि रु. 7,64,300/- सह-अभियुक्त अशोक सिंह के साथ मिलकर याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में फंसाने का कथित अवैध कार्य अशोक सिंह के इकबालिया बयान पर आधारित है, जो पुलिस द्वारा दिनांक 06.06.2021 पर हिरासत में दर्ज किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की उसके साथ संलिप्तता के बारे में कोई स्वीकृति नहीं है। ट्रक चालकों से अवैध रूप से धन निकालने के आरोप के समर्थन में कोई सामग्री एकत्र नहीं की गई है यधपि याचिकाकर्ता को आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के लिए जांच के बाद पुलिस केवल मोबाइल नंबर 8709496552 की रिकॉर्डिंग के आधार पर अशोक सिंह की बातचीत पर ही कार्रवाई की गयी, जिसके आधार पर उक्त अशोक सिंह और याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए मेरे अनुसार उचित

जांच की आवश्यकता थी। अशोक सिंह के साथ मिलीभगत से किए गए कथित कार्य को याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा जांच के आधार पर वॉट्सऐप संदेश ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता स्थापित किए बिना, फोरेंसिक रिपोर्ट द्वारा समर्थित किए बिना साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा किसी भी व्यक्तिपरक संतुष्टि के बिना, केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक आरोपों के आधार पर, यह अभिनिर्धारित करना कि जांच करना व्यावहारिक नहीं था, केवल आरोपी अशोक सिंह की बातचीत के आधार पर धारणा बनाने के बराबर होगा। अशोक सिंह, जिनकी अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा गवाही नहीं ली गई है, जिसमे ने अनुशासनात्मक प्राधिकरी द्वारा पहली बार प्रश्नगत आदेश में पारित किया गया है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था।

22. ***तारसेम सिंह (ऊपर)*** मामले के फैसले में, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब प्राधिकरण की यह राय है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, तो इस तरह के निष्कर्ष को प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि पर दर्ज किया जाएगा, और यह वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। उपरोक्त मामले में, आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जांच को छोडने के कारणों को समुचित सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

23. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विभागीय कार्यवाही किए बिना ही सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लेते हुए इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा की गई कि केवल किसी अधिकारी के विरुद्ध अवैध धन वसूली का मामला दर्ज हो जाना ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि नियमित विभागीय जांच कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को पहले ही निर्दोष पाया जा चुका है और जांच में यह भी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से

भुगतान किए जाने वाले रिश्वत की राशि को अशोक सिंह के खाते में जमा कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के खाते में एक भी पैसा जमा नहीं किया गया है और प्रतिवादियों ने उक्त तथ्य से इनकार नहीं किया है।

24. यहां तक कि अशोक सिंह के पुलिस द्वारा 06.06.2021 पर दर्ज किए गए इकबालिया बयान में भी34/36 पुलिस द्वारा 06.06.2021 पर दर्ज किए गए सिंह ने न तो याचिकाकर्ता का नाम लिया है और न ही उसके साथ अपनी भागीदारी को स्वीकार किया है। मोबाइल नंबर-8709496552, जिस पर पूरी बातचीत की गई और जांच का आधार अशोक कुमार सिंह का है, न कि याचिकाकर्ता का।

25. याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक हलफनामे में, पैराग्राफ नं. 5, ने विशेष रूप से कहा है कि जाँच अधिकारी द्वारा अंतिम प्रपत्र दाखिल करके जाँच के बाद उसे आपराधिक मामले में पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है और इसे विद्वान जिला न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस आधार पर और उसमें निहित आक्षेपित आदेश, पत्र संख्या 4460 दिनांक 25.06.2021 में निहित आक्षेपित आदेश और बाद के आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

26. अनुच्छेद 311 में अंतर्निहित धारणा यह है कि संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमता में कार्यरत व्यक्ति की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया के पालन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को साबित करने की सीमा सभी मामलों में उच्च है, लेकिन विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) में सुदृढ़ किया गया है। संवैधानिक निर्देश का पालन किए बिना शक्ति का आह्वान दंड के आदेश को अमान्य कर देगा जैसा कि ***तुलसीराम पटेल (उपरोक्त)*** के मामले में माना गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा

अनुच्छेद 311 (2) (बी) को लागू करने के लिए "*बाध्यकारी परिस्थितियों*" पर पहुंचने के लिए एक भी उदाहरण का हवाला नहीं दिया गया है या उस पर भरोसा नहीं किया गया है, तथ्यों या यहां तक कि एक विश्वसनीय औचित्य द्वारा पूरी तरह से असमर्थित है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बर्खास्तगी का आदेश विषम, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के आयात के पूरी तरह से विपरीत है।

27. यहाँ ऊपर स्वीकार किए गए तथ्यों और चर्चा को ध्यान में रखते हुए और तुलसीराम पटेल (उपरोक्त) और वेद मित्तर गिल (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए, पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के दिनांक 25.06.2021 पत्र संख्या 4460 में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण, डी. आई. जी. द्वारा पारित दिनांक 08.07.2021 ज्ञापन संख्या 1708 में निहित बर्खास्तगी का आदेश, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए भोजपुर जिला आदेश संख्या 2140 दिनांक 10.07.2021 के तहत परिणामी आदेश, एवं इस आदेश में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 02.11.2022 के अपीलीय आदेश को ठीक करने की आवश्यकता है।

28. याचिकाकर्ता, स्वतंत्र है, यदि वह चाहता है/सलाह प्राप्त करे, तो उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल कर सकता हैं, ताकि उसके मामले पर विधि के अनुसार विचार किया जा सके।

29. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

30. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

नीरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।